साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गाँव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

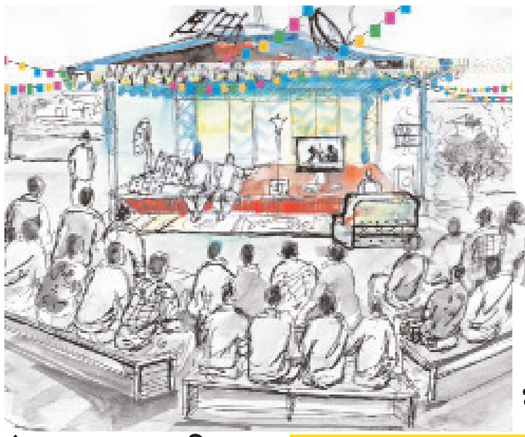

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 13-19 दिसंबर 2021, वर्ष-7, अंक-37

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मध्यप्रदेश में नवाचारः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियमों में किया संशोधन

पंचायतों में अब टैक्स वसूलेंगे महिला स्व-सहायता समूह

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल।

महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार महिला स्व-सहायता समूह को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तय किया है कि पंचायतों में कर वसूलने का काम महिला स्व-सहायता समूह को दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियमों में संशोधन कर दिया है।

अब पंचायत चाहें तो जल कर, स्वच्छता कर और साप्ताहिक बाजार की दुकानों से शुल्क संग्रहण का काम इन्हें दिया जा सकता है। कर वसूलने पर समूहों को कमीशन मिलेगा। महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कोरोना काल में बड़ी संख्या में मास्क बनवाए गए और पूरक पोषण आहार तैयार करने जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा गया। समूहों ने स्थानीय स्तर पर कई उत्पाद भी तैयार किए, जिनकी बड़ी मांग है। इसे बाजार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मिशन काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समूहों को नए क्षेत्रों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग काम कर रहा है। वहीं, अब नियमों में संशोधन करके तय कर दिया है कि पंचायतें चाहें तो कर एकत्र करने का काम इन्हें दे सकती हैं।

-जल कर, स्वच्छता कर और साप्ताहिक बाजार से शुल्क का काम दे सकती हैं पंचायत

कोरोना संक्रमण की रोकथाम का पालन नहीं करने पर पंचायतों ने जुर्माना लगाया था। 36 लाख जुर्माना वसूल किया गया। इससे यह विचार आया कि जब पंचायतें इतने कम मानव संसाधन में जुर्माना वसूल सकती हैं तो फिर मानव संसाधन मिल जाएं तो अन्य कर भी लिए जा सकते हैं। अब नियमों में संशोधन करके यह व्यवस्था बना दी है कि पंचायतें महिला स्व-सहायता समूह को कर एकत्र करने का काम दे सकती हैं। इसके लिए समूह को कमीशन मिलेगा, जो कुल संग्रहित कर के हिसाब से तय होगा।

उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पहला प्रयोग रहा सफल

बालाघाट, नरसिंहपुर, उज्जैन सहित कुछ अन्य जिलों की बड़ी पंचायतों में यह प्रयोग सफल रहा है। दो सौ से ज्यादा नल जल योजना का संचालन अब समूह कर रहे हैं। उपभोक्ताओं से प्रतिमाह जल कर लिया जा रहा है। इसी तरह स्वच्छता कर, बिजली और साप्ताहिक बाजार की दुकानों से शुल्क संग्रहण काम भी इन्हें दिया जाएगा। इससे पंचायतों और समूह के सदस्यों को भी आर्थिक लाभ होगा। इधर, पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पंच, सरपंच और जनपद उम्मीदवारों ने एक करोड़ रुपए की बकाया राशि भरने की हामी भर दी है। यह बिजली विभाग की राशि है। जिसकी वसूली के लिए कर्मचारी पिछले पांच साल से चक्कर लगा रहे थे। 187 ग्राम पंचायतों में करीब एक करोड़ रुपए रिकवरी की उम्मीद है। दरअसल, यह रिकवरी इसलिए हो पा रही है क्योंकि पंचायत चुनाव में इस बार नए सिरे से आरक्षण नहीं हुआ है। दोबारा से उन्हीं प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है। ऐसे में एनओसी की जरूरत होगी। जो बिना बकाया चुकाए नहीं मिलेगी।

सिंधिया ने कहा- ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खुलेंगे पांच ड्रोन स्कूल

किसानों को मिली उड़ान

संवाददाता। भोपाल

ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपातकाल में यह ड्रोन संजीवनी की तरह काम करते हैं। इतना ही नहीं, यह खेतों में कीटनाशक का छिड़काव से लेकर सीमा पर सुरक्षा तक में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

वहीं केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस ड्रोन मेला से तकनीकी क्षमताओं का विकास तो होगा ही साथ ही यह रोजगार के भी अवसर खोलेंगे। उन्होंने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर व सतना में पांच ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा भी की। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह ने इसे कृषि क्षेत्र में बहुउपयोगी बताया है। मेला में प्रारंभिक तौर पर 11 कंपनियों के ड्रोन का प्रदर्शन किया गया था। इसमें से ज्यादातर कृषि आधारित थे।

किसानों का बचेगा पैसाः शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाएंगे। ड्रोन एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जिसका उपयोग जन-कल्याण एवं सुशासन में किया जा सकता है। मेले ग्वालियर की प्राचीन परंपरा हैं, पर ग्वालियर में ड्रोन मेले के रूप में अद्भुत मेला लगा है। यह ड्रोन मेला एक मेला भर नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में किया जा सकता है। इससे किसान हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। यह तकनीक खर्चीली भी कम है। ड्रोन तकनीक से 25 प्रतिशत तक खाद की बचत होती है।

- ग्वालियर में लगा प्रदेश का पहला ड्रोन मेला: सीएम बोले-ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में मप्र को अग्रणी बनाएंगे
- तोमर बोले-कृषि के क्षेत्र में सुरक्षा, उर्वरक बचत और उत्पादन बढ़ाने में ड्रोन तकनीक विशेष लाभकारी
- विकास व जन-कल्याण के क्षेत्र में करेंगे ड्रोन तकनीक का उपयोग
- हरदा में लोगों को अचल संपत्ति का अधिकार ड्रोन के माध्यम से मिला

ड्रोन किसानों के लिए क्रांतिकारीः तोमर

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि उच्च तकनीक और मजबूत अर्थ-व्यवस्था के साथ श्रेष्ठ भारत के निर्माण की सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन तकनीक किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हो रही है। उन्होंने पिछले साल टिड्डी दल के आक्रमण का हवाला देते हुए कहा कि ड्रोन तकनीक से इस पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया। स्वामित्व योजना भी इसी तकनीक की बदौलत सफल रही है। कृषि के क्षेत्र में मानव सुरक्षा, उर्वरक बचत और कृषि उत्पादन बढ़ाने में ड्रोन तकनीक विशेष लाभकारी रही है।

जिंदगी में आएगा बदलावः सिंधिया

केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन मेला ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसके माध्यम से हम नई क्रांति के साक्षी बने हैं। आगे आने वाले समय में ड्रोन तकनीक से विश्व की अर्थ-व्यवस्था और किसानों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में मप्र देश का अव्वल राज्य है। प्रधानमंत्री की सोच है कि ऐसी तकनीक हो जो जन-जन की जिंदगी में बदलाव लाए। रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में ड्रोन तकनीक क्रांतिकारी साबित हो रही है। युवाओं के लिए विकास के नए अवसर लेकर आई है। ड्रोन तकनीक से 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने नियमों को आसान बनाया गया है।

ड्रोन की सेवाओं का प्रदर्शन

ड्रोन मेला में भाग लेने आईं एक दर्जन कंपनियों ने अपनी-अपनी सेवाओं का प्रदर्शन किया। साथ ही ड्रोन के हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्य चकित कर दिया। ड्रोन मेले में थ्रॉटल एयरोस्पेस सिस्टम बैंगलुरू, एस्टेरिया एयरोस्पेस लिमिटेड बैंगलुरू, मारूत ड्रोन्स हैदराबाद, ड्रोन डेस्टिनेशन नई दिल्ली, एग्री उड़ान प्रा.लि. अहमदाबाद, ग्वालियर पुलिस, बीसा सिम्यट नई दिल्ली सहित अन्य कंपनियों ने उर्वरक बीज छिड़काव व परिवहन, सर्विलांस, वनीकरण, जरूरी वस्तुओं का परिवहन इत्यादि का अपने-अपने ड्रोन से प्रदर्शन किया।

कृषि उपज उपार्जन एवं समर्थन मूल्य पर क्रय का विनियमन विधेयक लाने की तैयारी

सावधान! मध्यप्रदेश में अब एमएसपी पर घटिया उपज खरीदी तो होगा कारावास

दस हजार रुपए या उपार्जित उपज के समर्थन मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा

संवाददाता, भोपाल। मप्र सरकार एमएसपी पर उपज खरीदने की व्यवस्था को सख्त बनाने जा रही है। दरअसल, प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में ऐसा अनाज उपार्जन केंद्रों द्वारा खरीद लिया जाता है, जिसे भारतीय खाद्य निगम या नागरिक आपूर्ति निगम अमानक बताकर लेने से इंकार कर देते हैं। जबकि, किसानों को भुगतान हो चुका होता है। ऐसे में सरकार को इसका वित्तीय भार उठाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने मप्र कृषि उपज उपार्जन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय का विनियमन विधेयक-2021 लाने की तैयारी में है। इसमें गुणवत्ताहीन उपज खरीदने पर जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान रहेगा।

खरीदी का बन चुका रिकॉर्ड

दो साल पहले समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक गेहूं खरीदकर मप्र देश में रिकॉर्ड भी बना चुका है। धान का उपार्जन भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इस वर्ष 40 लाख टन से अधिक धान की खरीद संभावित है। ग्रीष्मकालीन मूंग भी पहली बार लगभग आठ लाख टन खरीदी गई है। सरकार इसमें हजारों करोड़ रुपए व्यय कर रही है, जिसका इंतजाम आरबीआई से ऋण लेकर किया जाता है।

घटिया अनाज से हुआ घाटा

नागरिक आपूर्ति निगम पर लगभग 55 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। केंद्र सरकार जब सेंट्रल पूल में गेहूं, धान, चना, मूंग आदि उपज ले लेती है तो फिर उसका भुगतान होता है, लेकिन दो-साल से गुणवत्ताहीन उपज खरीदने के मामले सामने आ रहे हैं।

पड़ोसी राज्यों पर नजर

इसी तरह सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों से गेहूं और धान बिकने के लिए आने के मामले भी सामने आए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था को सख्त बनाने का निर्णय लिया है। अब सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी उपार्जन केंद्र में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा और गड़बड़ी पाए जाने पर सामग्री और वाहन को जब्त भी कर सकेगा। औसत गुणवत्ता से कम की उपज खरीदने पर दस हजार रुपए या उपार्जित उपज के समर्थन मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेगा मध्यप्रदेश का जवाहर मॉडल

तीन साल में जैविक खाद किसानों को रसायनिक खाद से दिलाएगी मुक्ति

जैविक खाद से कम खर्च में बढ़ जाएगी अन्नदाताओं की पैदावार

जेएनकेवी ने जवाहर जैव उर्वरक नाम से 15 बायो फर्टिलाइजर बनाए

प्रवीन नामदेव | जबलपुर

किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगे रसायनिक खादों के चलते खेती की लागत बढ़ने की रहती है। मध्य प्रदेश की कृषि यूनिवर्सिटी ने किसानों की इसी समस्या का हल खोजा है जैविक खाद बनाकर। बेहद सस्ते ये जैविक खाद अपनाकर किसान पहले साल ही रासायनिक खादों में 25 प्रतिशत की कटौती करके 15 से 20 प्रतिशत अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तीन से चार साल में किसान पूरी तरह से रसायनिक खाद से छुटकारा पाकर सिर्फ जैविक खाद से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि **जबलपुर के विभागाध्यक्ष एवं बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट यूनिट इंचार्ज डॉ. एनजी मिश्रा जागत गांव हमार** के इस अंक में किसानों को बता रहे हैं कि जैविक खेती से किसान कैसे कृषि लागत को कम कर सकते हैं।

15 तरह के जैविक खाद बनाए

जेएनकेवी ने जवाहर जैव उर्वरक नाम से 15 तरह के बायो फर्टिलाइजर बनाए हैं। इसमें हवा से नाइट्रोजन अवशोषित करने सहित पोटाश, फास्फोरश, जिंक, बीजोपचारित, पत्तियों या गेहूं-धान के अवशेष को गलाने के जैव विघटक शामिल हैं। किसान भाई तीन साल तक इसका प्रयोग करते रहें तो चौथे साल रसायनिक खाद से निजात मिल जाएगी। पहले साल 25 प्रतिशत रसायनिक खादों की कमी कर इसका प्रयोग करें, दूसरे साल 50 प्रतिशत, तीसरे साल 75 फीसदी और चौथे साल पूरी तरह से रसायनिक खाद का उपयोग बंद कर सकते हैं।

किसानों को होगा फायदा

जैविक खाद से फसल उत्पादन के दोहरे लाभ हैं। पहला तो किसान सस्ती और टिकाऊ खेती कर पाएगा। दूसरा उसके उत्पाद जैविक होने की वजह से उसे मुंहमांगी कीमत बाजार में मिलेगी। पहले साल ही किसानों को 15 से 20 प्रतिशत अधिक उत्पाद मिलेगा। जैविक खाद का प्रयोग करके भी किसान रसायनिक खाद के प्रयोग की तुलना में अधिक उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं।

दो तरह के जैविक खाद

जेएनकेवी ने दो तरह के जैविक खाद बनाए हैं। पहला पाउडर जैविक खाद और दूसरा तरल जैविक खाद। पाउडर जैविक खाद का उपयोग किसान भाई 6 महीने की अवधि तक कर सकते हैं। वहीं तरल जैविक खाद का उपयोग किसान एक साल तक कर सकते हैं। बस ध्यान इतना देना है कि इसे छाएं में स्टोर करके रखें। पाउडर जैविक खाद 200 ग्राम के पैकेट में 40 से 50 रुपए में और तरल जैविक खाद एक लीटर मात्रा में 300 रुपए तक की कीमत में आता है। किसानों को इस पर 15त्न तो एनजीओ या बड़ी मात्रा में खरीदने वाली संस्थाओं को 20 फीसदी तक छूट दी जाती है।

जैविक खाद का आसान तरीका

जवाहर जैविक खाद का उपयोग करना बेहद आसान है। पाउडर से बीच उपचार प्रति 15 ग्राम प्रति किलो की दर से किसान भाई कर सकते हैं। वहीं तीन से चार किलो प्रति एकड़ 50 किलो गोबर, केंचुआ खाद या नम मिट्टी में मिलाकर कर खेत में कर सकते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई करनी होती है। इसी तरह तरल जैविक खाद की 10 एमएल मात्रा प्रति किलो बीज को गुड़ के साथ घोल तैयार कर उपचारित कर सकते हैं। जबकि खेत में दो लीटर प्रति एकड़ 50 किलो गोबर के खाद में मिक्स कर बिखेर दें। इसके बाद हल्की सिंचाई कर दें। किसान चाहें तो टपक सिंचाई विधि से डेढ़ से दो लीटर तरल जैविक खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर 10 से 15 दिन बाद टपक सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं।

पत्तियों को सड़ाने का उपाय

जवाहर जैव विघटक का प्रयोग कर किसान धान, गेहूं, तम्बाकू, चना, बैंगन, गन्ना, केला, टमाटर, चुकंदर, मिर्ची,आलू, सोयाबीन, प्याज, मटर, सूर्यमुखी, अदरक आदि के अवशेष और पत्तियों को सड़ा कर खाद में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए जवाहर जैव विघटक-1 या दो का किसान प्रयोग कर सकते हैं। किसान चाहे तो पूरे खेत में दो लीटर प्रति एकड़ की दर से जवाहर जैव विघटक को पानी में मिलाकर छिड़काव कर जुताई कर दें। नहीं तो 4 फीट चौड़ा, तीन फीट गहरा और 10 फीट लंबाई का गड्ढा तैयार कर दो से तीन टन कचरे को दो लीटर तरल जैव विघटक की मदद से सड़ा सकते हैं।

इस तरह करता है असर

- प्रोडक्शन यूनिट में 15 तरह के बॉयो फर्टीलाइजर बनाए जा रहे हैं। इसके प्रयोग से 10से 25 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ जाता है।
- जवाहर राइजोबियम, एजोटोबेक्टर, एसिटोबेक्टर और जवाहर नील-हरित शैवाल हवा से नाइट्रोजन खींच कर पौधे तक पहुंचाते हैं।
- जवाहर पीएसबी और जवाहर माइकोराइजा से फसलों को फास्फोरस उपलब्ध होता है। सभी फसलों और सब्जियों में ये लाभदायक होगा।
- जवाहर केसएसबी से पोटाश की कमी दूर की जा सकती है। सभी फसलों के लिए ये उपयोगी है।
- जवाहर जेडएसबी से जिंक की कमी पूरी होगी। ये भी सभी फसलों के लिए उपयोगी है।
- जवाहर स्यूडोमोनास, जवाहर बायोफर्टिसॉल और जवाहर ईएम सभी फसलों व सब्जी, फल के फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता अच्छी और बढ़वार ठीक होता है।
- जवाहर ट्राइकोडर्मा ये सभी फसलों के लिए अच्छा है। बीज उपचार करने से लेकर जड़ व पत्ती रोग को भी दूर करता है।
- जवाहर जैव विघटक-1 कवकयुक्त और जवाहर जैव विघटक-2 जीवाणुयुक्त के प्रयोग से फसलों के अवशेष और पत्तियों को सड़ाकर जैविक खाद बना सकते हैं।

बोरियों में उगाएं 29 तरह की फसल-सब्जियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना किसानों की आय दोगुना करने का है और उस दिशा में लगातार प्रयोग हो भी रहे हैं। उनका यह सपना मध्य प्रदेश का जवाहर मॉडल पूरा कर सकता है। इस मॉडल के जरिए किसान अपनी बेकार और बंजर पड़ी जमीन से भी आमदनी कर सकते हैं। घर की छतों पर भी यह मॉडल कारगर है। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने आधा एकड़ जमीन में बोरियों में 29 तरह की फसलें और सब्जियां लगाई हैं। दावा है कि इस टेक्नीक का इस्तेमाल कर किसान आधा एकड़ खेत से सालभर में 50 हजार तक का मुनाफा कमा सकते हैं। जवाहर मॉडल किसानों की आय कैसे बढ़ा सकता है। इस बारे में जबलपुर कृषि विवि के विशेषज्ञ डॉ. मोनी थॉमस ने दिए अहम सुझाव। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का संकल्प 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। इसके लिए कोई मॉडल नहीं था। हमारे स्टूडेंट्स इस पर 6 साल से रिसर्च कर रहे थे। जवाहर मॉडल के जरिए गरीब किसान, जिसके पास बेकार से बेकार जमीन है, वह भी हर हफ्ते कुछ न कुछ आमदनी निकाल सकता है।

अरहर के साथ बोरी में लगा सकते हैं धनिया

मान लीजिए अगर आप अरहर की बोवनी करते हैं तो इसके लिए एक बोरी में 45 किलो मिट्टी और गोबर की जरूरत पड़ती है। अरहर का पौधा जुलाई में बोया जाता है। फसल सालभर में तैयार होती है। एक एकड़ में 1230 बोरियों में अरहर के पौधे लगते हैं। अरहर के साथ बोरी में धनिया लगाकर दो बार फसल ले सकते हैं। एक बार में एक बोरी से 500 ग्राम धनिए की पत्ती तैयार होती है। अरहर के साथ अलग बोरी में हल्दी या अदरक भी बो सकते हैं। अरहर की छांव में अदरक और हल्दी की अच्छी उपज होती है। एक बोरी में 50 ग्राम बीज लगता है और 6 महीने में दो से ढाई किलो तक उपज तैयार हो जाती है। एक पौधे से दो से ढाई किलो अरहर पैदा होती है।

अब जुताई का झंझट भी नहीं

जवाहर मॉडल खासियत यह है कि इसमें न तो अधिक पानी की जरूरत पड़ती है और न ही खेत जुताई का भी झंझट। जवाहर मॉडल में 29 किस्म की फसलें और सब्जियां लगाई जा सकती हैं। इस मॉडल को अपनाने वाले किसानों पर निर्भर करता है कि वह मिश्रित खेती में कौन सी फसल की बुआई करना चाहते हैं। इसी से आमदनी तय होगी।

लाख का उत्पादन भी कर सकते हैं

अरहर के पौधे पर लाख का कीड़ा भी चढ़ाकर मुनाफा कमा सकते हैं। कीड़ा नवंबर में चढ़ाते हैं। 8 महीने में एक पौधे से 350 ग्राम के लगभग लाख प्राप्त होता है। इसकी कीमत 350 रुपए प्रति किलो तक होती है। एक पौधे से 5 किलो जलाऊ लकड़ी भी मिल जाती है। लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े टहनियों से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है, जिसे काटी गई टहनियों से खुरच कर निकाला जाता है। लाख का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पॉलिश और सजावट की चीजों को तैयार करने में किया जाता है।

615 महिला किसानों ने अपनाया मॉडल

जबलपुर जिला पंचायत के सहयोग से 615 महिला किसानों ने इस मॉडल को अपनाया है। महिला किसानों ने इसे बाड़ी में लगाया है। पिछले दिनों नाबार्ड के जिला मैनेजर व चीफ मैनेजर आए थे। उन्होंने जवाहर मॉडल अपनाने और छोटे किसानों को लोन देकर इस तरह मध्य प्रदेश में खेती को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है।

आधा एकड़ से 50 हजार की कमाई

जवाहर मॉडल अपना कर किसान आधा एकड़ में कम से कम 50 हजार रुपए की कमाई कर सकता है। इस विधि में उसका खेत कभी खाली नहीं रहता है और हर हफ्ते कोई न कोई समय से पूर्व उत्पाद तैयार मिला है। जैविक उत्पाद होने से फसल भी अच्छी होती है और उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। जवाहर मॉडल को किसान का एटीएम माना गया है। मतलब एनी टाइम मनी, जब भी किसान चाहे, कोई न कोई उत्पाद बाजार में बेचकर 200 से 400 रुपए रोज कमा सकता है।

तस्वीर बदलने की चाह में अब पारंपरिक कृषि से हटकर नए प्रयोग कर रहे उन्नत किसान

स्ट्रॉबेरी, सेब, अंजीर, थाई पिंक अमरूद और ड्रैगन फ्रूट की खेती की ओर बढ़ा रुझान

भोपाल के किसान कर रहे यूनिक खेती

विदिशा व भोपाल जिले के कई गांव में बड़े रकबे में अनार की खेती भी की जा रही, खेत के पास गौशाला में गाय भी पाली जा रही हैं, गोबर गैस प्लांट लगाने की तैयारी

संवाददाता। भोपाल

पीढ़ियों से गेहूं, चना, सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों का रुझान यूनिक खेती की ओर तेजी बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह मौसम और उपज लागत भी है। भोपाल और उससे सटे इलाकों में किसान स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अंजीर, अनार, ड्रैगन फ्रूट सेव, थाई पिंक अमरूद की खेती भी कर रहे हैं। जिले में पपीते की खेती का रकबा भी बढ़ा है। भोपाल से सटे दबोटी गांव के किसान राजमोहन अग्रवाल ने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी के 24 हजार पौधे लगाए हैं।

स्ट्रॉबेरी के पौधों के बीच में खाली जगह में उन्होंने अंजीर के 350 पौधे भी लगाए हैं। स्ट्रॉबेरी के टिश्यू कल्चर प्लांट पुणे से लाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी की 6 से 8 इंच ऊंची झाड़ियां होती हैं। इसे सितंबर में लगाते हैं, मार्च तक यह फसल तैयार हो जाती है। उद्यानिकी सलाहकारों के मुताबिक क्षेत्र के कई किसान यूनिक खेती अपनाना चाहते हैं। रायसेन रोड पर कई किसान थाई पिंक अमरूद की खेती कर रहे हैं। शेखपुरा गांव समेत जिले के कई गांवों में किसान पपीते की खेती करने लगे हैं। विदिशा और भोपाल जिले के कई गांव में अनार की खेती भी की जा रही है।

काले गेहूं की खेती का बढ़ा चलन

एडवांस खेती करने वालों में शुमार किसान शशि भूषण सिंह तोमर का कहना है कि बैरसिया और भोपाल से सटे रायसेन के गांवों में किसान काले गेहूं की खेती भी कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके इस्तेमाल का चलन भी बढ़ा है।

जैविक पद्धति को दे रहे बढ़ावा

स्ट्रॉबेरी, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप यानी कम अवधि की फसल है। यहां बाजार में ज्यादातर स्ट्रॉबेरी रतलाम से आती है। दूरी ज्यादा होने के कारण रास्ते में उसके खराब होने का खतरा रहता है। दबोटी भोपाल से सिर्फ 45 किमी दूर है। इतनी कम दूरी पर हमारे शहर और आसपास के लोगों को ताजी और उम्दा स्ट्रॉबेरी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। खेत के आसपास गौशाला में 40 गाय भी पाली जा रही हैं। गोबर गैस प्लांट भी लगाया जाएगा। पूरी खेती जैविक पद्धति पर आधारित हो।

यूनिक खेती के लिए अच्छी किस्म के बीज, पौधों का चयन करना जरूरी है। इसके पहले किसान मिट्टी का भी परीक्षण कर लें। जलवायु अनुसार पौधों का रोपण करें। इससे उनकों कभी भी घाटा नहीं होगा। अब परंपरागत खेती को छोड़कर किसाना नवाचा कर रहे हैं।

-डॉ. आरके जायसवाल, प्रिंसिपल साइंटिस्ट फल अनुसंधान केंद्र

हमारे क्षेत्र के कई किसान यूनिक खेती अपनाना चाहते हैं। रायसेन रोड पर कई किसान थाई पिंक अमरूद की खेती कर रहे हैं। शेखपुरा गांव समेत जिले के कई गांवों में किसान पपीते की खेती करने लगे हैं। विदिशा और भोपाल के कई गांव में अनार की खेती की जा रही है।

सुबोध सहस्त्रबुद्धे, सलाहकार, उद्यानिकी

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

12 जिलों की बुझेगी प्यास, 10 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई

- -केन-बेतवा मिलकर सूखे बुंदेलखंड को करेंगी हरा-भरा, परियोजना को लिंक करने की मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर
- -कृषि क्षेत्र में होगा विकास, लाखों लोगों का दूर होगा जल संकट
- 44,605 करोड़ की लागत से नदियों को जोड़ा जाएगा, राष्ट्रीय परियोजना होगी, केंद्र का योगदान 90 फीसदी

प्रशासनिक संवाददाता। भोपाल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन-बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खास बात यह है कि इसका 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके तहत 176 किमी की लिंक कैनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के सागर-विदिशा सहित 12 जिलों को पानी मिलेगा। इसके साथ ही 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा कर लिया जाएगा। नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इसका भूमि पूजन अगले महीने झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की तैयारी है। इससे पहले मोदी ने दोनों राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मप्र को बड़ी राहत

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से नॉन मानसून सीजन में मप्र को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इस योजना से सागर-विदिशा समेत मप्र के 8 जिलों को पानी पहुंचाना है। इसे लेकर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा

सिंचाई का लक्ष्य तय

प्रोजेक्ट के दोनों फेज से सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावॉट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना में दो बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावॉट है।

12 जिलों को मिलेगा फायदा

परियोजना से बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के 12 जिलों को पानी मिलेगा। मध्यप्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी को पानी मिलेगा। वहीं, उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी।

सरकार ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 44,605 करोड़ की लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90 फीसदी होगा। अगले 8 साल में केन-बेतवा नदी को जोड़ने का यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट में 39317 करोड़ रुपए का योगदान करेगी।

वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुंदेलखंड को 44 हजार 605 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात केन-बेतवा लिंक योजना के रूप में दी है। यह बुंदेलखंड के विकास के लिए अद्भुत कार्य है। इस योजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा। इससे यहां 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा 62 लाख व्यक्तियों को पीने का पानी मिलेगा।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धन्यवाद के पात्र हैं। बेतवा विकास की नदी है। सागर स्मार्ट सिटी का कार्य नगर को नया स्वरूप प्रदान करेगा। लाखा झील को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने का कार्य महत्वपूर्ण है।

गोपाल भार्गव, मंत्री

केन-बेतवा लिंक योजना बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगी। इससे पूरा बुंदेलखंड समृद्ध और संपन्न होगा। बुंदेलखंड के गांव-गांव में घरों तक पाइप लाइन बिछाकर पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। अब किसी को भी पानी के लिए दूर तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। भारत रत्न अटल जी के सपने को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं।

भूपेंद्र सिंह, मंत्री

लाल परेड मैदान में आयोजित होगा चार दिवसीय वन मेला

कोरोना में वनौषधियों की उपयोगिता पर रहेगा केंद्रीत

विदेशी विशेषज्ञ भी किए गए हैं आमंत्रित

भोपाल। राजधानी का लाल परेड मैदान एक बार फिर वन मेले से गुलजार होने जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कोरोना कॉल के दौरान वनौषधियों की उपयोगिता विषय पर केंद्रीत होगा। वन विभाग एवं राज्य लघु वनोपज संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेले में दूसरे देशों के परंपरागत विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन इस बार 22 से 26 दिसंबर के बीच होगा। इसमें प्रदेश के परंपरागत वैद्यों के साथ ही दूसरे प्रदेशों के वनोषधि स्टॉल प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र होंगे। चूंकि कोरोना कॉल में वनोषधियां काफी कारगर साबित हुई हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता व उपलब्धता पर आमजन यहां विदेशों से भी जुटे विशेषज्ञों के अनुभवों से अवगत हो सकेंगे। क्योंकि इसमें वन समितियों के सदस्य, ग्रामीण, औषधियों के जानकार रहेंगे। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से संग्रहीत की गई दुर्लभ जड़ी-बूटियों के स्टाल लगाए जाएंगे। जिनमें वनौषधियों का विक्रय भी होगा। इस बार नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ म्यांमार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

केन-बेतवा लिंक : बुन्देलखण्ड में विकास का नया सवेरा

डॉ. आनंद प्रकाश शुक्ल
वरिष्ठ पत्रकार

देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का नदी जोड़ो सपना पूरा होने लगा है। देश की पहली नदी केन और बेतवा आपस में जुड़ेगी। इसके लिये भारत सरकार ने सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। केन-बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी से बुन्देलखण्ड की गरीबी और पिछड़ापन दूर होगा। यहां विकास का सूरज उगेगा और पलायन भी रूकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस परियोजना के साकार होने से केवल मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। परियोजना की मंजूरी में भले ही देर लगी हो किन्तु यह सही है कि इससे बुन्देलखण्ड में औद्योगिक निवेश, रोजगार के सृजन और पेयजल की सुविधा के साथ-साथ सिंचाई क्षमता में भी अपार वृद्धि और सौर उर्जा उत्पादन का काम शुरू होगा। राज्य में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार वास्तव में विकास के लिए डबल इंजन की तरह काम कर रहे हैं।

इस ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय के लिए वास्तव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के वषज़् में इस प्रकार के निर्णय को ऐतिहासिक ही कहा जायेगा। अभी तक पूवज़्वतीज़् सरकारों में इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए थे। यदि गौर से देखा जाये तो इस निर्णय में नये बुन्देलखण्ड के साथ-साथ नये भारत की तस्वीर साफतौर पर दिखाई दे रही है। इस निर्णय से एक बार फिर यह साबित हो गया कि भाजपा की मोदी सरकार विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहतर निणज़्यों की बुनियाद लगातार रख रही है।

केन-बेतवा लिंक की शुरूआत मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के आते ही वर्ष 2003 में शुरू हो गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय लेने में समय भले ही लगा हो किन्तु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इच्छा अंतत: परिणाम में बदल गयी। केन्द्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ केन्द्रीय कैबिनेट का आभार माना। उन्होंने यह कहा कि परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान और एक नया सवेरा है। बता दें कि इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपये बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की मिलेगी सुविधा, 103 मेगा वाट जल विद्युत और 27 मेगा वाट सौर ऊर्जा उत्पादित होगी। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में भी खुशहाली और सम्पन्नता आयेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 44 हजार 605 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने पर मध्यप्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जिलों को लाभ मिलेगा। परियोजना से बुंदेलखंड में भी खुशहाली और सम्पन्नता आएगी। वास्तव में देखा जाए तो समूचे बुन्देखण्ड में इस समय घर-घर खुशहाली और उम्मीदों की रौशनी दिखाई दे रही है। परियोजना के लिये केंद्रीय समथज़्न के रूप में 39 हजार 317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36 हजार 290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किया गया है। यह भी सही है इस परियोजना से भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। बताते चलें कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अन्तर्गत मूर्त रूप लेने वाली केन-बेतवा लिंक देश की पहली राष्ट्रीय परियोजना है। परियोजना की विस्तृत डी.पी.आर तैयार करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, उत्तरप्रदेश शासन और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर दोनो राज्यों के लाखों लाख परिवार उम्मीद लगाए हुए थे। सच्चाई तो यह है कि आने वाले दिनों में अब बुन्देलखण्ड की पहचान विकास और समृद्धि की ही होगी। इस परियोजना से एक नहीं अनेक लाभ होंगे। कुछ प्रमुख लाभों का उल्लेख किया जाना प्रासंगिक भी होगा।

परियोजना के मूर्तरूप लेने पर बुन्देलखंड क्षेत्र को सूखाग्रस्त होने से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। भू-जल स्तर की स्थिति में सुधार आयेगा। इसका लाभ आस-पास के जिले पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन को मिलेगा। परियोजना से 103 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पूर्णरूप से मध्यप्रदेश ही करेगा। जल आपूर्ति होने पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगीकरण एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्थानीय स्तर पर आमजन में आत्म-निभज़्रता आएगी तथा क्षेत्र से लोगों का पलायन रुकेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यदि जिलेवार स्थिति पर नजर डालें तो पन्ना जिले में 70 हजार हेक्टेयर, छतरपुर में 3 लाख 11 हजार 151 हेक्टेयर, दमोह में 20 हजार 101 हेक्टेयर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी में 50 हजार 112 हेक्टेयर, सागर में 90 हजार हेक्टेयर, रायसेन में 6 हजार हेक्टेयर, विदिशा में 20 हजार हेक्टेयर, शिवपुरी में 76 हजार हेक्टेयर एवं दतिया जिले में 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा।

वास्तव में केन-बेतवा नदी को जोड़ने वाली इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से क्षेत्र विकास की रफ्तार बढ़ जायेगी। बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध होने के साथ-साथ विकास और आत्मनिर्भरता की और तेज गति से आगे बढ़ेगा। औद्योगिक निवेश में वृद्धि और पर्यटन में गति मिलने से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। पेयजल की स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ सिचाई की क्षमता बढ़ेगी और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। किसानों की खुशहाली और प्रतिव्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा सरकारें आने वाले नये भारत की आधारशिला रख रहीं हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत के साथ अब उसे पूरा करने में जन सहयोग की आवश्यकता है। सत्ता और समाज जब किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो वह परिणाम तक पहुंचकर समृद्धि की राह खोल देता है। म.प्र. की जनभागीदारी इसका उत्तम उदाहरण है।

सुदूर अंचलों में सौर ऊर्जा बन रही है, गेम चेंजर

आनंद सोलंकी-
घनश्याम केशरवानी

ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में भी नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई उद्योग नीति में भी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन से जुड़ी इकाईयों की स्थापना को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। राज्य के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सौर ऊर्जा खासी मददगार साबित हो रही है। राज्य में ऐसे कई हिस्से हैं जहां परम्परागत तरीके से विद्युत की व्यवस्था नहीं हो सकी है, उन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सोलर पम्प गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों में ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा, पेयजल व्यवस्था, ग्रामों और मजरे-टोलों के विद्युतीकरण में सोलर एनर्जी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पिछले तीन वषोज़् में सोलर इनजीज़् का उपयोग कर सोलर पम्पों के जरिए 70 हजार 800 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, वहीं 2 लाख 81 हजार 798 से अधिक परिवारों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और दूरस्थ पहुंचविहीन अविद्युतीकृत गांवों और मजरे-टोलों के 80 हजार 917 घरों का सौर विद्युतीकरण किया गया है।

प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई उद्योग नीति में भी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन से जुड़ी इकाईयों की स्थापना को प्राथमिकता की श्रेणी में क्रेडा द्वारा राज्य में पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में 59 हजार सोलर कृषि पम्पों की स्थापना की गई। सोलर सिंचाई पम्पों से लगभग 70,800 हेक्टयेर रकबा सिंचित हुआ है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक पिछले 5 वर्षों में 3 एवं 5 हासज़् पॉवर के 96 हजार सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना की गई, जिससे लगभग एक लाख 15 हजार 200 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौर सिंचाई सामुदायिक परियोजना सतही जल गेत के निकट बनायी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में 31 सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से लगभग 977 किसानों की 1250.49 हेक्टेयर भूमि में सिचाई सुविधा का लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं में 88 सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 222 सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना में 306 सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किये गए हैं, इसके माध्यम से 2166 किसानों की 2414 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है।

पिछले तीन वर्षों में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए नदी नालों के निकट स्थित खेतों को सिंचित करने के लिए 88 वृहद सोलर पम्प स्थापित किये गए हैं। जिनके माध्यम से 1250.49 हेक्टेयर सामुदायिक कृषि रकबा सिंचित हो रहा है। इसके अलावा सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के तहत 3083 गौठानों में सोलर पम्प स्थापित कर पशुओं के लिए पेयजल और चारागाहों में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था की गई है। गौठानों में 2489 तथा चारागाहों में 594 सोलर पम्पों की स्थापना अब तक की गई है। सोलर पेयजल योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में पहुंच विहीन गांवों में 4187 सोलर ड्यूल पम्प स्थापित कर 2 लाख से अधिक परिवारों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतगज़्त 2100 ड्यूल पम्प स्थापित कर ग्रामीण अंचलों के घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूतिज़् की व्यवस्था की गई है। इस योजना में 12 मीटर एवं 9 मीटर ऊंचाई पर 10 लीटर क्षमता की पानी टंकी स्थापित कर घरों में पेयजल की आपूतिज़् की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 81,798 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों में 1350 गांवों और कस्बों के चौक-चौराहों, हाट बाजारों में 1415 सोलर हाईमास्ट लाईट स्थापित की गई हैं। इसी तरह दूरस्थ पहुंच विहीन क्षेत्रों में जहां बिजली का तार खींचकर बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां के गांवों और मजरे टोलों के 80 हजार 917 घरों में सोलर लाईट के माध्यम से प्रकाश की व्यस्था की गई है। इन्हें मिलाकर सोलर संयंत्रों के माध्यम से 941 गांवों के एक लाख 38 हजार से अधिक घरों का सोलर विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य के 458 स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए 2.56 मेगावाट के ऑफग्रिड सोलर पॉवर प्लांटों की स्थापना की गई है। राज्य में अब तक कुल 1388 शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों अस्पतालों में सोलर लाईट से बिजली पहुंचाई गई है, जिससे वहां प्रकाश की व्यवस्था के अनुसार जीवन रक्षक मशीनें और वैक्सिन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर हेतु विद्युत प्रदाय किया गया है, इस उपलब्धि के लिए क्रेडा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में सोलर पम्प के जरिए जहां किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है, वहीं ग्रामीणों को पेयजल सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। इन क्षेत्रों में किसान अब दोहरी फसल ले रहे हैं, इससे उनकी आमदनी में काफी इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार की अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा किसानों को सोलर सिंचाई पम्प रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

शिप्रा नदी: मां मजबूर और बेटे मगरूर होकर उसे कर रहे गंदा

जिस नदी शिप्रा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंति खंड में मिलता हो, जिस शिप्रा के कारण उज्जैन को धर्मनगरी होने का गौरव प्राप्त हो तथा जिस शिप्रा को मोक्षदायिनी कहा जाता हो, यदि उसकी सफाई के लिए साधु-संतों को धरना देना पड़े, तो यह शासन, प्रशासन के साथ-साथ नागरिक समाज के लिए भी शर्मनाक है। यूं तो शिप्रा ही नहीं बल्कि किसी भी छोटी-बड़ी नदी में गंदगी होना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है ही, किंतु यदि हमारी धार्मिक आस्थाओं और संस्कारों को सींचने वाली शिप्रा जैसी पवित्र नदी भी गंदगी से बजबजाती हो, तो फिर क्या कहा जाए। उज्जैन में शिप्रा किनारे स्थित दत्त अखाड़ा घाट पर धरना देने वाले 13 अखाड़ों के साधु-संतों की पीड़ा केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे नागर समाज की पीड़ा होनी चाहिए। शिप्रा जिस अवंतिका नगरी को संस्कृति-सिक्त बनाती है, उस नगरी की गिनती भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनियाभर के प्राचीनतम नगरों में होती है। जितना प्राचीन उज्जैन है, उतनी ही प्राचीन मां शिप्रा। यदि हम अपनी इतनी महत्वपूर्ण धरोहर को भी स्वच्छ नहीं रखते हैं तो यह हमारे मनुष्य होने की पहचान पर प्रश्न चिह्न है। कहना न होगा कि हिमालय से निकलने वाली सदानीरा मां गंगा के शुद्धीकरण को लेकर जैसी चर्चा देशभर में छिड़ती रही है, वैसी सुर्खियां शिप्रा को कभी नहीं मिलीं। किंतु इसका आशय यह नहीं कि सरकार, प्रशासन और नागरिक समाज इसकी ओर ध्यान न दें। यद्यपि मप्र सरकार ने नर्मदा का पानी लाकर शिप्रा को प्रवाहमान बनाए रखने का संकल्प लिया था और उसे कुछ हद तक सिद्ध भी करके दिखाया, किंतु वह प्रयास भी खेत रहा। अब वर्ष में एकाधिक बार स्नान-पर्व पर नर्मदा का पानी शिप्रा में छोड़कर उसे कृत्रिम रूप से कुछ दिनों के लिए प्रवाहमान बना दिया जाता है और पर्व के बीतते ही शिप्रा फिर गंदगी और बदबू से बजबजाती पानी की एक पतली धार बनकर रह जाती है।

मछुआरों की आर्थिक सुदृढ़ बनाने प्रदेश में बनेगी नई मछुआ नीति

मछुआरों की आर्थिक सुदृढ़ बनाने प्रदेश में बनेगी नई मछुआ नीति

विशेष संवाददाता। भोपाल

जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वल्लभ भवन में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक उन्नति, आदिवासी भाईयों को विशेष अधिकार और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मछुआ संशोधन नीति बनाने को लेकर ड्राफ्ट बनाया जाए। जिसमें पड़ोसी राज्य की मछुआ नीति का भी अध्ययन किया जाए, उनके हितकारी बिंदुओं को ड्राफ्ट में लेते हुए विशेषज्ञ व्यक्तियों की सलाह भी ली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन हो इसके लिए जरूरी नीति और योजना बनानी होंगी और मछुआ समुदाय के युवाओं को इससे जोड़ना होगा।

मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि नई नीति बनाकर मध्य प्रदेश को देश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में नंबर वन बनाना चाहते हैं। मछली उत्पादन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं और संसाधनों को ठीक करना होगा। इसके लिए नई नीति बनाने में अच्छा काम कर रही मछुआ पालन समितियों, मत्स्य पालकों, मत्स्य विभाग के पूर्व अधिकारियों और मत्स्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे लोगों की राय लेकर नई संशोधन नीति की ड्राफ्टिंग करें ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मछुआ किसानों को मिल सके और प्रदेश में

मछली उत्पादन उत्पादन बढ़ाया जा सके। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा कर रही समितियों को देखकर और उनसे भी सीखने की जरूरत है। प्रदेश में बालाघाट ने देश में मछली उत्पादन में विशेष कार्य किया है, उनकी समितियों को अगले सप्ताह भोपाल बुलाया जाए उनसे मंत्री सिलावट खुद चर्चा करेंगे और उनका सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआ पालकों को जल्द से जल्द मछुआ क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। श्री सिलावट ने अधिकारियों से कहा कि मछुआ समाज के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया जाए, इसके लिए जल्द से जल्द सूची तैयार कर जानकारी दें।

नई समितियां होंगी गठित

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के मंत्री ने कहा कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जलाशयों में मत्स्य पालन के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर योजना तैयार करें। प्रदेश में संचालित सक्रिय समिति को प्रोत्साहित किया जाए और निष्क्रिय समितियों को खत्म कर नई समिति का गठन किया जाए। मंत्री ने प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में रहने वाले आदिवासी समाज को मछली पालन से जोड़ने के लिए अलग से नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज भी पहले से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ा रहा है। उनको भी मछली पालन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और वह मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार करने के भी निर्देश दिए।

14 जिलों में करा रहे झींगा पालन

बैठक में मौजूद मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि विभाग ने इस वर्ष 3.5 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त की है। धीमान और विभाग के संचालक भारत सिंह ने साढ़े तीन करोड़ रुपए की राशि का चेक मंत्री को सौंपा। मत्स्य महासंघ ने अगले वर्ष 6.5 करोड़ की रॉयल्टी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बैठक में मौजूद मत्स्य विभाग के संचालक भारत सिंह ने कहा कि हम जल्द ही नई मछुआ संशोधन नीति को लेकर पूर्व अधिकारियों, मत्स्य पालन समितियों और विशेषज्ञों से चर्चा कर ड्राफ्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बालाघाट की तरह प्रदेश के 14 जिले में झींगा पालन को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इससे लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी।

कुक्कुट पालन पर सरकार दे रही 50 प्रतिशत अनुदान

संवाददाता। भोपाल

मप्र पशुपालन विभाग द्वारा उन्नत पशुपालन आजीविका का बेहतर साधन के अंतर्गत कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। जिनमें कुक्कुटपालन भी है। इसका उद्देश्य कुक्कुटपालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, कडक़नाथ नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन करना है। उप संचालक, पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों जारी इन दोनों योजनाओं में रंगीन चूजों की बैकयार्ड और कडक़नाथ कुक्कुट इकाई वितरण की जानकारी दी जा रही है, जो सभी वर्गों के लिए है।

40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई - यह योजना सामान्य, अजा और अजजा सभी वर्ग के लिए है। इस योजना की इकाई लागत 2225 रुपए है। जिसमें बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजों का मूल्य प्रति इकाई (प्रति चूजा 45 रुपए) की दर से कुल 1800 रुपए, औषधि टीकाकरण रुपए 5 प्रति चूजा कुल 200 और परिवहन (चिक बॉक्स सहित) 225 रुपए कुल 2225 रुपए है। इसमें हितग्राही का अंशदान 25 प्रतिशत रहेगा और सरकारी अनुदान 75प्रतिशत रहेगा।

कड़कनाथ कुक्कुट इकाई

यह योजना भी सामान्य, अजा और अजजा सभी वर्ग के लिए है। इसकी इकाई लागत 4400 रुपए है। इसमें भी बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजे, खाद्यान्न, औषधि और परिवहन का प्रावधान है। जिसमें प्रति चूजा 65 रुपए की दर से 40 चूजों की लागत 2600 रुपए, औषधि/टीकाकरण (दर 5 रु प्रति चूजा) कुल 200 रुपए परिवहन (चिक बॉक्स सहित) 210 रुपए कुक्कुट आहार 48 ग्राम प्रति पक्षी, प्रति दिन, 30 दिवस के लिए कुल आहार 58 किलो, 24 रुपए प्रति किलो कुल 1390 रुपए कुल 4400 रुपए है। इसमें भी हितग्राही का अंशदान 25 प्रतिशत रहेगा और सरकारी अनुदान 75 प्रतिशत रहेगा।

-सवाई माधौपुर को भी इससे जोड़ने की कवायद

माधव-कूनो नेशनल पार्क बनेगा नया पर्यटन सर्किट

खेमराज मौर्य, शिवपुरी।

कूनो में चीते और माधव नेशनल पार्क में टाइगर के पुनर्वास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं जिससे अंचल में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। कूनो और माधव नेशनल पार्क नए पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। माधव नेशनल पार्क में टाइगर के आने के बाद टाइगर कोरिडोर भी बनाया जाएगा जिससे टाइगर कूनो तक का सफर कर सकेगा। अब इस नए सर्किट से पड़ोसी प्रदेश के सवाई माधौपुर को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सवाई माधौपुर के कलेक्टर राजेंद्र किशन के साथ बैठक की और नई संभावनाओं पर चर्चा की।

बैठक में सवाई माधोपुर-शिवपुरी पर्यटन सर्किट विकसित करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही वहां कलेक्टर को 25 दिसंबर ग्वालियर में होने जा रहे तानसेन समारोह के लिए भी आमंत्रित किया गया। बैठक में जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति समिति शिवपुरी के सदस्य अरविंद सिंह तोमर, फिल्म निर्माता एवं पर्यटन से जुड़े अनिल पाटिल एवं जिले के होटल तथा टूर एंड ट्रेवल से जुड़े समीर गांधी, राकेश यादव कूनो रिवर कैंप भी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बताया कि यह पर्यटन सर्किट बन गया तो दोनों जिलों की अर्थव्यवस्था को बहुत बूस्ट मिलेगा।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

शिवपुरी, कुनो एवं माधव शिवपुरी तथा ग्वालियर आने वाले 50 प्रतिशत और सवाई माधोपुर आने वाले 50 प्रतिशत पर्यटक दोनों स्थानों की विजिट करें तो पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। शिवपुरी प्रतिनिधि मंडल ने माधव नेशनल पार्क, भदैया कुंड, जिला संग्रहालय छतरी, तात्याटोपे स्मारक, जॉर्ज पंचम हंटिंग प्वाइंट, सुरवाया गढी, बॉम्बे कोठी, प्राकृतिक जल नीति, सेलिंग क्लब, माधव नेशनल पार्क, वहां आने वाले विदेशी प्रवासी पक्षी व वन्य जीवन के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इसी प्रकार कूनो, ओरछा और ग्वालियर के पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के संबंध में भी बिंदुवार जानकारी दी।

पड़ोसी होने के नाते सीखने की ललक यहां खींच लाई: कलेक्टर

इस अवसर पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों, होटल संचालकों एवं गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने पर्यटन सर्किट विकसित करने को लेकर अपने सवाल एवं जिज्ञासाओं को रखा। कलेक्टर शिवपुरी एवं कलेक्टर सवाई माधोपुर ने सभी के सवालों के जवाब दिए। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि सवाई माधोपुर से पड़ोसी के नाते प्रगाढ़ता तथा सीखने की ललक उन्हें यहां खींच लाई है। उन्होंने आशा व्यक्त कि इस प्रकार के प्रयासों से टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की दिशा में सफलता मिलेगी। बैठक में डीएफओ टाइगर प्रोजेक्ट महेंद्र शर्मा, सहायक निदेशक पर्यटन मधुसूदन सिंह, डीएफओ पर्यटन संदीप कुमार, होटल संचालक, गाइड प्रतिनिधि, टूर एंड ट्रेवल्स तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने उपस्थित अतिथियों को शिवपुरी की प्रसिद्ध लकड़ी की कलाकृतियां भी भेंट की। इसी प्रकार सवाई माधोपुर कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को सवाई माधोपुर पर्यटन से जुड़ी पुस्तकें उपहार में दी।

-पौष्टिक बिस्किट बनाने का प्लान वन विभाग ने बनाया

आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाएगा महुआ का बिस्किट

संवाददाता, होशंगाबाद।

खाद्यान्य गेहूं, मूंग, धान व चना की पैदावार में अव्वल नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में अब जल्द ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र केसला में प्रमुख वनोपज महुआ से बिस्किट बनाए जाएंगे। इस बिस्किट के कारोबार से 100 से अधिक आदिवासी परिवार आत्मनिर्भर हो सकेंगे। जिस महुआ से शराब बनाई जाती है उससे अब पौष्टिक बिस्किट बनाने का प्लान वन विभाग ने बनाया है। आदिवासी परिवार की महिलाओं को बिस्किट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केसला के सहेली गांव की महिलाओं के लिए जल्द ही बिस्किट बनाने वाली यूनिट से जोड़ा जा रहा है। तैयार बिस्किट की खपत के लिए पर्यटन स्थल पचमढ़ी, तवा नगर, मड़ई , तिलक, सेंदूर भीलट देव तथा तथा अन्य बाजारों से जोड़ा जाएगा। महुआ से बिस्किट बनाने की बात जब प्रदेश के राज्यपाल को बताई गई, तब उन्होंने ही सुझाव दिया है कि तैयार बिस्किट को पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध कराए जाएं।

बाजार भी मिलेगा

वन विभाग का मानना है कि पोषक तत्व से भरपूर कुपोषण की मार झेल रहे आदिवासियों के बच्चों को उनके पसंदीदा बिस्किट खाने को मिलेंगे। बिस्किट के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस कारोबार से सैंकड़ों आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाने की पहल की जा रही है।

331 गांवों में आदिवासी

जिले में 331 गांवों में हजारों की संख्या में आदिवासी रहते हैं। जिसमें सबसे अधिक आदिवासी केसला ब्लाक में 133 गांव में रहते हैं। केसला ब्लाक का सहेली गांव सड़क किनारे है। वहां पर वन विभाग का महुआ का बहुत बड़ा गोदाम भी है। जिसमें क्षेत्र के आदिवासियों से समर्थन मूल्य पर महुआ का क्रय किया जाता है। इसी महुआ से बिस्किट बनाए जाने हैं।

यूनिट की बात सुनकर खुश आदिवासी

जब से महिलाओं को बताया गया कि महुआ से बिस्किट बनाने की यूनिट जल्द डाली जाएगी तभी से महिलाओं में खुशी बनी हुई है। सहेली गांव की वन धन स्वसहायता समूह की महिलाओं ने प्रारंभिक प्रशिक्षण भी लिया है। यहां की महिला सुखवती, रामवती, श्यामाबाई, सरोज, शीला, उर्मिला, भागवती, सोनम आदि का कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि महुआ से बिस्किट बनाए जाने हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिस्किट बनना शुरू हो।

इनका कहना है

केसला ब्लाक में महुआ के पेड़ बहुत अधिक है। जिनसे महुआ की पैदावार बहुतायत में होती है। इस इलाके में महुए से बनी शराब का प्रचलन भी ज्यादा है। अब जल्द ही इनका बिस्किट बनाने में किया जाएगा। सैंकड़ों आदिवासी महुआ को समर्थन मूल्य पर बेचते भी हैं। प्रधानमंत्री वन धन विकास कार्यक्रम के तहत सहेली गांव में विभाग द्वारा महुआ से बिस्किट बनाने की यूनिट डाली जाना है।

लालजी मिश्रा, डीएफओ, होशंगाबाद

महुआ से बिस्किट बनाने का प्लान वन विभाग ने तैयार कर उस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। इससे आदिवासियों के जीवन में एक अलग ही बदलाव आएगा। महिलाओं की आय बढ़ेगी।

मनोज सरयाम, अपर कलेक्टर, होशंगाबाद

महुआ में बहुत अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने की भी शक्ति होती है। बीते सालों में बच्चों में कुपोषण बढ़ा है क्षेत्र के आदिवासियों की आहार श्रृंखला में महुए से बने बिस्किट शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करेंगे। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की जो समस्या है वो इनसे दूर होगी।

आरआर सोनी, पूर्व उपवन पाल

बोवनी के 20-25 दिन बाद हाथ से या हैंड व्हील से करे निंदाई

गेहूं में खरपतवार प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों ने दी सलाह

-किसानों को दूसरी निदांई बोवनी के 35-40 दिन बाद करना चाहिए

संवाददाता, टीकमगढ़।

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति और डॉ. यूएस धाकड़ द्वारा किसानों को गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन पर तकनीकी सलाह दी गई। गेहूं की फसल के खरपतवार दो भागों में बांटे गए हैं। चौड़ी पत्ती वाले बथुआ, संजी, दूधी, कासनी, जंगली पालक अकरी, जंगली मटर, कृष्णनील, सत्यानाशी, हिरनखुरी आदि और सकरी पत्ती वाले नींदा-मोथा, कांस, जंगली जई, चिरैया बाजरा व अन्य घासे गेहूं की फसल में उगते हैं। यदि खरपतवारों का समय पर नियंत्रण न करने पर उपज में 25-35 प्रतिशत तक कमी आ जाती है। यह कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश एवं स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होती है। गेहूं में नींदा नियंत्रण तीन प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम सस्य क्रिया के अंतर्गत मेंड़ों एवं नालियों को साफ सुथरा रखें, उचित फसल चक्र अपनाएं, उचित खेत की तैयारी और सफ-सुथरे स्वस्थ्य बीज का उपयोग करें।

यांत्रिक विधि अंतर्गत बोवनी के 20-25 दिन बाद हाथ से या हैंड व्हील से निंदाई-गुड़ाई बोवनी के 35-40 दिन बाद करना चाहिए और दूसरी निदांई-गुड़ाई बोवनी के 35-40 दिन बाद करना चाहिए। अंत में रासायनिक विधि के अंतर्गत नींदानाशक रसायनों का नींदा की उपलब्धता को देखते हुए छिड़काव करें। चौड़ी पत्ती वाले नींदा नियंत्रण के लिए 2,4 डी 160 से 200 ग्राम और सकरी पत्ती वाले नींदा के लिए आइसोप्रोटयूरान 300 ग्राम प्रति एकड़ और सकरी एवं चौड़ी पत्ती दोनों के लिऐ सल्फोसल्फूरान 75 प्रतिशत डब्ल्यू जीमेटसल्फूरान 5 प्रतिशत डब्ल्यू जी 16 ग्राम प्रति एकड़ या क्लोडीनाफोप प्रोपरजिल 15 प्रतिशत मेटसल्फूरान मिथाइल 1 प्रतिशत डब्ल्यू पी, 160 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

किसानों को तकनीकी सलाह

इधर, कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार,डॉ. आरके प्रजापती और जयपाल छिगारहा द्वारा जिले के किसानों को रबी फसल तकनीक की सलाह दी जा रही है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 4.5 दिन बादल रहने की संभावना है। साथ ही कहीं-कहीं। बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे मौसम में कीट व्याधि एवं बीमारियां फसलों में लगने की अधिक संभावना है जिसके कारण फ़सल उत्पादकता कम हो सकती है। अत: किसानों को ऐसे मौसम में रबी की फसलों में लगने वाले रस चूसक कीट माहू कीटों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 एसएल की 5 मिली प्रति लीटर या 7.8 मिली प्रति टंकी पानी मिलाकर छिड़काव करने से रस चूसक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसी प्रकार चने की इल्ली की रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 30.35 मिली प्रति टंकी या प्रोफेक्स सुपर 1.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करके कम किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिक तापमान एवं अधिक आपेक्षिक आद्रता के कारण फफूंद जनित बीमारियां जैसे डैंपिंग ऑफ, अगेती झुलसा और जड़ सड़न रोग इत्यादि का प्रकोप बढ़ जाता है।

-कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में विश्व मृदा दिवस पर बोले विशेषज्ञ

उर्वरता में सुधार लाने कृषि तकनीकों का प्रयोग करें

संवाददाता, रीवा।

कृषि विज्ञान केंद्र रीवा द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रो. एसके पयासी अधिष्ठाता कृषि कॉलेज रीवा ने उद्घाटन किया। कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रथम आगमन पर पुष्पुगुच्छ देकर केन्द्र प्रमुख एवं वैज्ञानिको द्रारा स्वागत किया गया। प्रो. पयासी ने किसानों, ग्रामीण महिलाओं व छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वे सरकार की मंशानुरूप अपने मृदा के स्वास्थ व उर्वरता में सुधार लाने के लिए हर संभव कृषि तकनीकों का प्रयोग करें। मृदा को जीवित बनाए रखें। केन्द्र के प्रमुख डॉ. एके पांडेय ने कहा कि मृदा की दसा एवं स्वास्थ दोनों सुधारना है जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में मृदा स्वास्थ व पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में तकनीकी जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा वैज्ञानिक अखिलेश कुमार पटेल ने हरी खाद के साथ-साथ खेत के अवशेषों के प्रबंनधन की आवश्यकता पर जोर दिया। जिससे मृदा मे कार्बनिक प्रदार्थों के स्तर और मृदा कि जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। डॉ. राजेश सिंह उद्यान वैज्ञानकि ने फलों में किस प्रकार खाद का प्रबंधन किया जाए इस पर जानकारी दी। डॉ. अखिलेश कुमार पौध संरक्षण वैज्ञानिक ने इस अवसर पर मृदा को टिकाऊ व स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाने के लिए अवश्यक फसल चक्र का प्रयोग गर्मी मे गहरी जुताई, बीज उपचार, जैव कीटनाशियों का प्रयोग एवं फसल अवशेष प्रबंधन आदि विषयों पर तकनीकी जानकारी दी। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. सीजे सिंह और डॉ. संजय सिंह ने खाद बनाने की प्रक्रिया पर जानकारी दी। इस अवसर पर केन्द्र के एमके मिश्रा ने मृदा स्वास्थ प्रबंधन पर जोर दिया। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. किंजलक सिंह, डॉ. स्मिता सिंह, संदीप शर्मा, डॉ. केएस बघेल, मंजू शुक्ला, और ऋषभ ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजय सिंह ने किया।

अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच जरूरी

संवाददाता, टीकमगढ़।

अधिक उत्पादन तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए संतुलित खाद का उपयोग जरूरी है। यह तभी संभव है जब खेत में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी हो। यह बात मिट्टी की रासायनिक जांच करके पता लगाई जा सकती है। मिट्टी की जांच के लिए खेत की मिट्टी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में भेजा जाता है। यह बात कृषि विज्ञान केंद्र अनूपपुर की मृदा विज्ञान विशेषज्ञ डा. अनिता ठाकुर ने कही।

उन्होंने बताया कि इसके द्वारा मृदा की प्रकृति तथा उर्वरता स्थिति निर्धारित की जा सकती है। मृदाओं की क्षारीयता तथा लवणीयता समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। फसलों पर आवश्यक खनिज पोषक तत्वों की कमी तथा अधिकता संबंधित लक्षणों को देखकर परामर्शदायी कार्य के लिए सिफारिश करने में सहायता मिलती है। बाग-बगीचों एवं फुलवारी लगाने के उददेश्य से मिट्टी की उपयुक्तता की जानकारी हो जाती है। उन्होंने बताया कि सामान्य रूप से खेत में मिट्टी की प्रकृति स्थान-स्थान पर परिवर्तनशील रहती है, इसलिए मिट्टी की सामान्य प्रकृति के अनुसार ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से मृदा-नमूने लेना आवश्यक हो जाता है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत के 8-10 भागों का चयन करें। नमूना खेत के हर भाग से लिया गया हो। ध्यान रखें कि मिट्टी के नमूने के साथ कोई अन्य सामग्री न मिली हो। नमूना लेने के लिए सबसे पहले चुने स्थानों की ऊपरी सतह साफ कर लें। मिट्टी में घास, कचरा होने पर सही परिणाम नहीं आएंगे। अब खुरपी की सहायता से 6 से 9 इंच गहरा अंगेजी के टी आकार का गड्ढा बनाएं। गड्ढों के दानों सतहों की एक इंच मोटी परत निकालें। इस प्रकार के गड्ढे हर चुने स्थान पर बनाएं।

केंद्र सरकार के निर्देश पर सहकारिता विभाग बना रहा नई व्यवस्था

अब एसएमएस से किसानों को चलेगा पता मप्र में कहां और कितनी खाद

-सहकारी विपणन संघ के गोदामों में रखी खाद की स्थिति चलेगी पता

-किसानों को नकद विक्रय केंद्रों से खरीदने में रहेगी आसानी

प्रशासनिक संवाददाता। भोपाल

रबी फसलों के लिए किसान डीएपी और अब यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और केंद्र सरकार से लगातार आपूर्ति भी हो रही है। इसके बाद भी वितरण व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है।

सहकारी समितियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। इस व्यवस्था में सुधार के लिए अब सरकार नई व्यवस्था बनाने जा रही है। इसमें किसानों को एसएमएस के माध्यम से यह पता चलेगा कि राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के किस गोदाम पर कितना खाद उपलब्ध है। इसके आधार किसान समितियों पर दबाव बना सकेंगे कि जब संघ के गोदाम में खाद है तो वे उसे लेकर वितरित क्यों नहीं करा रहे हैं।

वहीं, जो किसान समितियों के डिफाल्टर हैं, वे सीधे नकद में खाद खरीद सकेंगे। प्रदेश में रबी फसलों की बोवनी होने के साथ ही अब यूरिया की मांग तेजी से बढ़ रही है। सहकारिता विभाग समितियों के माध्यम से अब तक तीन लाख 94 हजार टन से ज्यादा यूरिया की बिक्री कर चुका है। करीब 40 हजार टन यूरिया समितियों के पास उपलब्ध है। जबकि, पिछले साल इसी अवधि तक तीन लाख 78 हजार 187 टन यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया गया था। वहीं, डीएपी दो लाख 30 हजार 67 टन विक्रय किया जा चुका है।

यह सुविधा नि:शुल्क रहेगी

इससे उन किसानों को खाद लेने में सुविधा होगी, जो सहकारी समितियों का समय पर कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अपात्र हो गए हैं, वे खाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा नि:शुल्क रहेगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों को अधिक से अधिक सूचना और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर मार्कफेड को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सीधे जिलों को आवंटित की जा रही खाद

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार से जो खाद प्राप्त हो रही है, वो आवश्यकता के अनुसार सीधे जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिदिन छह से सात रेलवे रेक के माध्यम से यूरिया आ रही है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे खाद की मांग कम से कम एक सप्ताह पहले बताएं ताकि उसके हिसाब आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके।

समितियों के पास 19.2 हजार डीएपी

पिछले साल दो लाख पांच हजार 800 टन डीएपी किसानों ने इस अवधि तक लिया था। 19 हजार 200 टन डीएपी अभी भी समितियों के पास उपलब्ध है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बोवनी का काम समाप्त हो चुका है। अब किसानों को यूरिया की दरकार रहेगी। इसे देखते हुए दिसंबर के लिए केंद्र सरकार से सात लाख टन यूरिया की मांग की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार केंद्र सरकार से बात भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सहकारिता विभाग अब नई व्यवस्था भी बनाने जा रहा है। इसमें किसानों को एसएमएस के माध्यम से पता चलेगा कि विपणन संघ के किस गोदाम में कितनी मात्रा में खाद उपलब्ध है। संघ नकद में खाद विक्रय करता है।

किसानों को तहसील के नहीं लगाने पड़ेंगे फेरे

अब आनलाइन मिलेगी भू-अधिकार पुस्तिका

सरकार ने व्यवस्था को कर दिया आनलाइन

भोपाल। किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका (बही) के लिए अब तहसील कार्यालय और पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने इस व्यवस्था को आनलाइन कर दिया है। किसान आइटी सेंटर, एमपी आनलाइन, लोक सेवा केंद्र, कियोस्क सहित सरकार द्वारा तय अन्य माध्यमों से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भू-लेख पोर्टल से भू-अधिकार पुस्तिका की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर आवेदक को तय समयसीमा में दी जाएगी। राजस्व विभाग ने नियम संशोधित कर जारी कर दिए हैं। भू-अधिकार पुस्तिका दो पृष्ठों की होगी। इसके लिए किसान को 45 रुपए शुल्क देना होगा। यदि पुस्तिका अधिक पृष्ठों की हुई तो प्रत्येक पृष्ठ के लिए 15 रुपए अतिरिक्त देना होंगे। वहीं पुरानी भू-अधिकार पुस्तिका यथावत उपयोग में ली जा सकेंगी। विभाग ने प्रक्रिया तय की है। उसमें किसान को अपना आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, समग्र आइडी, पटवारी हल्का, सेक्टर क्रमांक आदि अभिलेख देने होंगे।

भू-अधिकार पुस्तिका जारी की जाएगी

इनके आधार पर सेवा प्रदाता आवेदक का आवेदन अपलोड करेगा। यदि आधार नंबर नहीं है, तो आवेदक का फोटो लेकर क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित कराया जाएगा। पटवारी तीन दिन में आवेदक का फोटो सत्यापित अथवा अमान्य करें। पटवारी द्वारा ऐसा नहीं किए जाने की दशा में फोटो को सही मानकर भू-अधिकार पुस्तिका जारी की जाएगी। आवेदन अमान्य होने या समयसीमा में निराकृत न होने पर आवेदक को अपील का अधिकार होगा। वह 30 दिन में पहली और 60 दिन में दूसरी अपील पेश कर सकेगा। उसका निराकरण 15 दिन में किया जाएगा।

प्रति क्विंटल 3200 रुपए तक में बासमती धान बिक रही

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बढ़ी बासमती की डिमांड

होशंगाबाद। नर्मदांचल की खरीफ की मुख्य उपज बासमती धान की मांग प्रदेश के बड़े शहरों के अलावा अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में धान की आवक और खरीदी में निरंतर तेजी जारी है। पिछले एक पखवाड़े से बासमती धान की आवक बढ़ने के साथ ही खरीदी भी बढ़ती जा रही है। मंडी में पंजीकृत एक

दर्जन से अधिक व्यापारी बोली लगा कर धान की खरीदी कर रहे हैं। जिसे पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान सहित प्रदेश के बड़े व्यापारियों की मांग पर वहां पहुंचाया जा रहा है। बासमती धान के दाम भी किसानों को तेज मिल रहे हैं। प्रति क्विंटल 3200 रुपए तक में बासमती धान बिक रही है।

बारदानों में भरकर रखी धान

व्यापारियों के द्वारा खरीदी गई धान। मंडी के प्रांगण में रखी हुई है। खुली हुई धान शेड में है। व्यापारियों की धान का परिवहन मांग के अनुसार धीरे-धीरे हो रहा है। अभी समर्थन मूल्य से धान खरीदी शुरू नहीं हुई तब और आवक बढ़ेगी उससे पूर्व व्यापारियों की धान का उठाव जरूरी है।

भोपाल के प्रोफेसर ने किया शोध तो हुआ खुलासा

औषधीय के साथ हल्दी में और भी कई विशिष्ट गुण

संवाददाता, भोपाल।

गुणकारी हल्दी में मौजूद एंटी आक्सीडेंट, एंटी फंगल व एंटी वायरल जैसे औषधीय गुणों से आज हर कोई परिचित है, पर इसमें और भी कई विशिष्ट गुण हैं, जिसकी सही तरीके से पहचान की जरूरत है। इसी क्रम में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईसर), भोपाल के बायोलाजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर विनीत के शर्मा ने हल्दी के पौधे का जीनोम अनुक्रम तैयार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने हर्बल जीनोमिक्स प्रक्रिया अपनाकर करीब दो साल तक अध्ययन किया।

विज्ञानियों का मानना है कि यह अपनी तरह का पहला शोध है। जीनोम अनुक्रम से अब हल्दी के संपूर्ण गुणों के बारे में पता किया जा सकता है और कई रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। हाल ही में प्रतिष्ठित नेचर ग्रुप की कम्युनिकेशंस बायोलाजी पत्रिका में प्रकाशित प्रो. शर्मा के शोध के मुताबिक हल्दी के पौधे में 17 हजार से अधिक जीन हैं। यह अनुक्रम हल्दी के औषधीय गुणों को लेकर होने वाले शोध कार्यों को गति देगा। साथ ही उसे मुख्यधारा की औषधीय पद्धतियों में शामिल करने में भी सहायक होगा।

जीनों के विकास का लगाया पता

प्रो. शर्मा ने शोध में 17 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। उन्होंने हल्दी के पौधे में द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, पादप फाइटोहार्मोन सिग्नलिंग और विभिन्नपर्यावरणीय जैविक और अजैविक तनाव प्रतिक्रियाओं से जुड़े जीनों के विकास का पता लगाया है। इसके मुताबिक हल्दी के पौधे जिन अणुओं की मदद से पर्यावरणीय तनाव झेलते हैं, वही हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं।

यह है जीनोम अनुक्रम

जीनोम अनुक्रम चार अक्षरों का एक कोड होता है। यह डीएनए के अंदर एडेनीन (ए), गुआनीन (जी), साइटोसीन (सी) और थाइमीन (टी) के रूप में रहता है। चारों अक्षर क्रम बदल-बदलकर सजे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर लें तो एजीसीटी, एसीजीटी, एटीजीसी... जीनोम अनुक्रम जीन्स बनाते हैं। विज्ञानी जीन्स का अध्ययन कर किसी भी पौधे का असली गुण पहचानते हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाता है। इस अनुक्रम से एलोपैथी व होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों में भी हल्दी के अधिकाधिक औषधीय गुणों पर आधारित उत्पादों के विकल्प खुलेंगे।

इनका कहना है

जीनोम अनुक्रम से अब हल्दी के संपूर्ण गुणों के बारे में पता कर सकते हैं। अब तक यह नहीं किया गया था। यह दुनिया का पहला जीनोम अनुक्रम है।

- प्रो. विनीत के शर्मा, विज्ञानी, बायोलाजिकल साइंसेज विभाग, आईसर, भोपाल

फसल लागत के अनुसार नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य, किसान परेशान

कपास की खेती से किसानों का मोहभंग

महंगी बिजली और मंडी टैक्स से उद्योग पर संकट

संवाददाता, भोपाल।

सफेद सोना यानी कपास से प्रदेश के किसान अब दूरी बनाने लगे हैं। वर्तमान में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी कर रहा है, लेकिन लागत के अनुसार किसानों को कीमत नहीं मिल रही। प्रदेश के छह जिलों में 20 केंद्रों पर खरीदी हो रही है। छिंदवाड़ा में भी सौंसर और पांढुर्ना में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य काम होने की वजह से किसान जिनिंग मिल संचालकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिनिंगों में प्रति क्विंटल कपास 8000 से 8500 रुपए में बिक रहा है। मध्यम लंबाई वाले कपास का समर्थन मूल्य 5726 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि लंबे रेशे वाले कपास का समर्थन मूल्य 6025 रुपए तय है। कीमत कम होने की वजह से सीसीआई के खरीदी केंद्रों में सन्नाटा है। प्रदेश में 1.70 प्रतिशत मंडी टैक्स देना होता है। मप्र की तुलना में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में मंडी टैक्स काफी कम है। महाराष्ट्र में 0.55 प्रतिशत मंडी टैक्स चुकाना होता है। टैक्स ज्यादा होने की वजह से प्रदेश में कपास की कीमत कम है, जबकि महाराष्ट्र में ज्यादा है। जिले के सक्षम किसान पड़ोसी राज्य में उपज बेच रहे हैं। स्थानीय जिनिंग मिलों में इक्का-दुक्का किसान ही आ रहे हैं।

कपास उद्योग पर संकट: जिनिंग उद्योग को प्रतिवर्ष 6 से 7 लाख क्विंटल कपास की जरूरत होती है, लेकिन कपास की आवक लगातार कम होती जा रही है। जिले के जिनिंग में जरूरत के अनुपात में केवल 15 प्रतिशत ही कपास की आवक है। मप्र में साढ़े नौ रुपए प्रति यूनिट और महाराष्ट्र में नौ रुपए प्रति यूनिट बिजली का टैरिफ है। जिनिंग मिल बंद होने के समय प्रदेश में यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में केवल कंज्यूम के हिसाब से बिल आता है। प्रदेश के जिनिंग संचालकों को 3 से 4 लाख रुपए अतिरिक्त बिल चुकाना पड़ता है।

कीमत ही नहीं मिल रही

महंगी बिजली और कपास की कम आवक ने जिले के उद्योगों को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां के जिनिंग संचालक महाराष्ट्र में उद्योग लगा रहे हैं। वर्तमान में सौंसर में छह और पांढुर्ना में चार जिनिंग मिलों का संचालन हो रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से कपास का उत्पादन आधा रहा गया है। लागत ज्यादा लगी है। कीमत कम मिल रही है। 11 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत मिलनी चाहिए।

कपास का बाजार में मूल्य ज्यादा मिल रहा है। सीसीआई का समर्थन मूल्य कम होने के कारण किसान मंडी प्रांगण में कपास बेचने नहीं आ रहे हैं। बाजार मूल्य अधिक मिलने के कारण किसान व्यापारियों को कपास बेच रहे हैं।

योगेश खानेकर, खरीदी अधिकारी, सीसीआई

मंडी टैक्स और महंगी बिजली होने की वजह से उद्योग बंद हो रहे हैं। मध्यप्रदेश के जिनिंग संचालकों को प्रतिमाह 3.50 लाख से 4 लाख रुपए अतिरिक्त बिल देना पड़ता है। जिनिंग का छह माह का सीजन होता है। मिल बंद होने पर भी लगभग 50 हजार रुपए प्रतिमाह बिल आता है। मजबूरी में पांढुर्ना से बंद कर महाराष्ट्र में उद्योग लगाना पड़ा है।

- अनिस शाह, जिनिंग, संचालक

बारिश से प्रभावित बाजरा भी समर्थन पर खरीदेगी सरकार

-ग्वालियर-चंबल संभाग में होती है बाजरा की ज्यादा खेती

-सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने केंद्रीय मंत्री से की बात

भोपाल। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर इस वर्ष कमजोर गुणवत्ता वाला बाजरा भी खरीदा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को विशेष अनुमति देगी। दरअसल, ग्वालियर-चंबल संभाग में अतिवर्षा की वजह से बाजरा की उपज प्रभावित हुई है। दाना भी छोटा रह गया। इसके कारण समर्थन मूल्य पर खरीद रोक दी गई थी। किसानों के हित को देखते हुए सहकारिता मंत्री डा. अरविंद सिंह भदौरिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से विशेष छूट देने की अनुमति देने को लेकर बात की। तोमर ने भरोसा दिलाया है कि वे केंद्र सरकार के स्तर पर निर्धारित एफएक्यू से कमजोर बाजरा खरीदने को लेकर सहमति बनवा लेंगे। इसे पीडीएस की दुकानों से सस्ता अनाज योजना के तहत वितरित किया जाएगा। 29 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के साथ-साथ राज्य सरकार ने बाजरा की खरीद भी प्रारंभ कर दी थी लेकिन कमजोर दाना होने की वजह से इसे रोक दिया गया है।

मंत्री ने भिजवाया पत्र

किसानों ने इसकी जानकारी सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को दी तो उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से चर्चा की और अपर मुख्य सचिव सहकारिता अजीत केसरी के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र भिजवाया। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष ग्वालियर-चंबल इलाके में अतिवर्षा के कारण बाजरा का दाना छोटा रह गया है। इसके कारण समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दो हजार 250 रुपए पर हो रही खरीद में इसे गुणवत्ताहीन बताया गया। अब सरकार की तैयारी है कि एफएक्यू में विशेष रियायत देते हुए बाजरा खरीद की अनुमति दी जाए। बाजरा की खेती ग्वालियर-चंबल संभाग में ज्यादा होती है।

आईसीएआर की रैंकिंग में मप्र के एक भी कृषि विवि को नहीं मिली जगह

-कृषि शिक्षा दिवस पर जारी हुई देश के 67 कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

संवाददाता, भोपाल।

देश के 67 कृषि विवि की अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि शिक्षा दिवस पर कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की है। जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शीर्ष 20 कृषि विवि में की सूची में मप्र का एक भी कृषि विश्वविद्यालय इस सूची में नहीं है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक जबलपुर में है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। यह कृषि विवि 1964 में स्थापित किया गया था। यह विवि कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का विवि है। यह भारत की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। दूसरा कृषि विवि ग्वालियर में है। जिसका नाम राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि है। दोनों विश्वविद्यालयों में स्नातक की उपाधि के लिए अर्थात बीएससी की डिग्री के लिए संयुक्त रूप से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसके साथ-साथ महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विवि की सीटों पर भी इसी परीक्षा के द्वारा चयन होता है।

टॉप कृषि विवि

दरअसल, भारत के पहले राष्ट्रपति और केंद्रीय कृषि मंत्री डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के दिन को साल 2016 से कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आईसीएआर ने भारत के कृषि विवि की रैंकिंग जारी की है। टॉप कृषि विश्वविद्यालय की लिस्ट में पहले नंबर पर हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। दूसरे नंबर पर नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। चौथे नंबर पर उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि और पांचवें नंबर पर पंजाब के लुधियाना में स्थित पंजाब कृषि विवि है।

देश के शीर्ष 20 विवि

शीर्ष 20 कृषि विवि में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, पंतनगर उत्तराखंड, पंजाब कृषि विवि, कृषि विज्ञान विवि, बैंगलोर, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कृषि विवि, कोयंबटूर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विवि, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एवं टेक्नोलॉजी, श्रीनगर, आचार्य एनजी रंगा कृषि विवि गुंटूर, तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विवि चेन्नई, केंद्रीय कृषि विवि इंफाल, चौधरी सरवन कुमार कृषि विवि पालमपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि, उदयपुर, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय रायपुर, कृषि विज्ञान विवि धारवाड़, गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विवि, लुधियाना, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि, भुवनेश्वर और आनंद कृषि विवि, आनंद शामिल हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

जागत गांव हमार
मध्यप्रदेश होगा बासमती धान का असली उत्पादक
जागत गांव हमार
फसल की लागत कम, मुनाफा ज्यादा के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी सरकार

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)